Government and private agencies during last three years; and

(b) what is the allocation made during the Seventh Five Year Plan period for each Programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) The details of major anti-poverty programmes undertaken by the Government and through private/voluntary agencies are as follows:

(i) *Integrated Rural Development Programme (IRDP)*:

The programme aims to assist the families below the poverty line in rural areas in taking up self-employment ventures in a variety of activities, through endowment of income generating assets funded by a combination of subsidy and institutional credit. An outlay of Rs. 2358.81 crores has been provided for this programme in the Seventh Plan and the target is to cover 20 million households including about 10 million old who are to be given supplementary dose of assistance. This programme is being implemented on 50:50 sharing basis between the Centre and the States.

(ii) *National Rural Employment Programme (NREP)*:

This programme envisages generation of additional employment opportunities for unemployed and under-employed persons in the rural areas, while simultaneously creating durable community assets for direct and continuing benefits to poverty groups and for strengthening the rural economy as well as improving the overall quality of life in rural areas. An outlay of Rs. 2487.47 crores has been provided for the programme during the Seventh Plan with the objective of generating 1445 million mandays of employment. This programme is being implemented on 50:50 sharing basis between the Centre and the States.

(iii) *Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP)*:

The basic objectives of this programme are to improve and expand employment opportunities for rural landless with a view to provide employment for at least one member of every landless labour household upto 100 days in a year and to create durable assets for strengthening the rural infrastructure which will lead to rapid growth. This programme is 100 per cent centrally funded. For the Seventh Plan, an outlay of Rs. 1743.78 crores has been provided for the programme and a target of 1013 million mandays of employment generation has been fixed.

बजट कार्यों में हिन्दी का प्रयोग

1972. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो राज्य जिनकी राज भाषा हिन्दी है बजट योजना तथा अन्य पत्र राजभाषा में भेजेंगे, उन पर राजभाषा में ही विचार किया जायेगा तथा उसी भाषा में ही उत्तर भी दिया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) और (ख) भारत सरकार के लिये राज्यों द्वारा भेजे गये बजटीय योजना और अन्य कागजातों पर विचार करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें अपनी अपनी राज्य विधान सभाओं में अपने बजट प्रस्तुत करने के लिये सक्षम है ।

देवनागरी में संचार उपकरणों का उपलब्ध कराया जाना

1973. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में देवनागरी लिपि का टेलेक्स, टेलीप्रिन्टर, कम्प्यूटर, पता लेखी

यंत्र, विद्युत टंकण यंत्र, शब्द संसाधक आदि डेढ़ दर्जन उपकरण उपलब्ध कराये गए हैं ; यदि हां, तो इनका अलग-अलग वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) इनकी सालाना मांग कितनी है ;

(ग) क्या इनकी अधिकांश मांग सरकारी विभागों द्वारा ही की जाती है ; और

(घ) सभी मंत्रालयों/विभागों में देवनागरी लिपि में इन उपकरणों के कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री श्री० के० आर० नारायणन) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड ने अपने विदेशी सहयोगकर्त्ता के सहयोग से देवनागरी लिपि में टेलेक्स-संदेश भेजने में सक्षम एक द्विभाषिक दूर-मुद्रक (टेलीप्रिन्टर) विकसित किया है, जिसकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता 8000 है ।

देवनागरी लिपि में प्रक्रिया के लिए अंग्रेजी कम्प्यूटरों पर हार्डवेयर में परिवर्तन करने तथा उस पर साफ्टवेयर उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। इस प्रौद्योगिकी के साथ, देवनागरी पर आधारित कम्प्यूटरों और शब्द संसाधकों के लिए वर्तमान कम्प्यूटरों तथा शब्द-संसाधकों पर साफ्ट-वेयर तथा हार्डवेयर में केवल मामूली सा परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी । अंग्रेजी कम्पयूटरों पर इस प्रकार के परिवर्तन पर केवल 1500 रु० की लागत आती है ।

(ख) वर्ष 1989-90 तक दूर मुद्रकों की मांग 18000 होने की संभावना है ।

उपर्युक्त (क) में उल्लिखित प्रौद्योगिकी को मद्दे नजर रखते हुए, किसी भी अंग्रेजी कम्पयूटर में उपर्युक्त सोफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उपलब्ध कराने पर उसका प्रयोग देवनागरी में प्रक्रिया करने के लिए किया जा सकता है । अतः यह मांग अधिकांशित: इस बात पर निर्भर करती है कि देवनागरी को बढ़ावा देने के लिए कितना प्रयास किया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जिन मंत्रालयों/विभागों को देवनागरी के साथ उपस्करों की आवश्यकता है, उन्हें क्रमशः अगले पाँच वर्षों में ये उपकरण उपलब्ध कर दिए जाएंगे ।

Aggrieved Pensioner

1974. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the pensioners are aggrieved in not getting a fair deal from the 4th Pay Commission;

(b) whether Government have received representations from individual pensioners and Pensioners' associations in this regard;

(c) whether Government propose to give some relief to old pensioners who are getting too meagre an amount to meet their medical expenses; and

(d) if so, what are the details of steps being taken or proposed to be taken to give relief to these pensioners who retired at least ten years ago and are drawing very meagre amount as pension?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AN PENSIONS (SHRI BIREN SINGH ENGTI): (a) to (d) The recommendations of the Fourth Central Pay Commission on pension are under consideration. In the meantime Government has decided to raise the minimum pension and minimum family pension to Rs. 375 against Rs. 300 recommended by the Pay Commission with effect from 1-1-1986.

Sale of spurious TV sets in the country

1975. SHRI THANGABAALU: Wi the PRIME MININSTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the sale of spurious TV sets of popular and well-known brands in the country; and